केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 51 गुरूवार 10 सितम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

डेंगू की दस्तक, एक महिला संक्रमित

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। कोतवाली रोड पर पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाली 36 साल की एक महिला में डेंगू की पुष्टि हुई है। महिला ने कानपुर की एक निजी लैब में जांच कराई थी। 7 सितंबर को आईजीएम एलाइजा जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। विभाग ने महिला और उसके परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया है।जानकारी के अनुसार, महिला को 4 सितंबर को बुखार और डेंगू जैसे लक्षण थे। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने डेंगू की आशंका में जांच कराने की सलाह दी थी। इसके बाद महिला ने उसी दिन कानपुर की एक निजी लैब में अपना सैंपल दिया। जांच रिपोर्ट 7 सितंबर को पॉजिटिव आई। फिलहाल महिला का इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम परिवार के सदस्यों और महिला के संपर्क में रहे लोगों से जानकारी जुटाएगी। करीबी लोगों के खून के नमूने लेकर जांच कराई जाएगी। सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने बताया कि महिला में डेंगू की पुष्टि हुई है। परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है।

गिट्टी लदे ट्रेलर की टक्कर से स्कूटी सवार वृद्ध की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बनकटी, (बस्ती)। लालगंज थाना क्षेत्र के महादेवा–लालगंज मार्ग पर सोहिला गांव के पास बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे गिट्टी लदे ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 70 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस और डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मुंडेरवा थाना क्षेत्र के हरदी कमोखर गांव निवासी रामप्रयाग (70) पुत्र जगई पिछले कई वर्षों से महादेवा–लालगंज मार्ग पर मकान बनवाकर किराने की दुकान चलाते थे। वह परिवार के साथ वहीं रहकर अपना व्यवसाय करते थे। बताया गया कि बुधवार को वह लालगंज की ओर एक दाह संस्कार में शामिल होने गए थे। दोपहर बाद स्कूटी से वापस महादेवा की ओर लौट रहे थे।

रामप्रयाग जैसे ही सोहिला गांव के पास पहुंचे, तभी सामने की दिशा से महादेवा की ओर आ रहे गिट्टी लदे ट्रेलर से उनकी स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वह स्कूटी समेत सड़क पर जा गिरे। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ह

हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद लालगंज थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी मय पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस दुर्घटना के कारणों और ट्रेलर के संबंध में जांच कर रही है।

घटना के बाद ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में भारी वाहनों के लगातार आवागमन को लेकर नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि महादेवा–लालगंज मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में गिट्टी लदे भारी वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 400 भारी वाहन प्रतिदिन इस मार्ग से आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इनमें से कई वाहन टोल टैक्स से बचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। लगातार भारी वाहनों के गुजरने से सड़क पर आम राहगीरों, बाइक और स्कूटी सवारों के लिए खतरा बढ़ गया है।

रामप्रयाग की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में एक पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। हादसे की सूचना के बाद परिजन घटनास्थल और पोस्टमार्टम स्थल की ओर दौड़ पड़े। परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल था। गांव में भी वृद्ध की मौत से शोक का माहौल बना हुआ है।

विधायक–सांसदों पर लगे 65 आपराधिक केस वापस होंगे ! सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली (आभा)। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान और पूर्व सांसदों–विधायकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को उनके खिलाफ दर्ज 65 आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने पाया कि इनमें से कोई भी मामला गंभीर या जघन्य अपराधों से जुड़ा हुआ नहीं था।

सीजेआई सूर्या कांत ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'किसी भी मामले में कोई गंभीर या जघन्य अपराध नहीं दिखता है, न ही ऐसा कोई संकेत है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं या बार–बार अपराध करते हैं। ये सभी मामले कोविड–19 महामारी के असामान्य दौर से जुड़े हैं जब जनता और जनप्रतिनिधि परेशान थे। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी और लॉकडाउन के दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से किए गए प्रदर्शनों और पुतला दहन पर दर्ज एफआईआर को चार मेन कैटेगरी में बांटा।

अगस्त 2021 में अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी कि नेताओं के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए राज्य सरकार को संबंधित

हाई कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ताकि शक्तियों का दुरुपयोग न हो। 2024 में जब हिमाचल सरकार हाई कोर्ट पहुंची थी, तब हाई कोर्ट ने 15 मामले वापस लेने की अनुमति दी थी, जबकि 45 मामले पेंडिंग रखे थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल वैभव श्रीवास्तव ने शीर्ष अदालत को बताया कि 45 लंबित मामलों में से 6 मामलों में आरोपी पहले ही डिस्चार्ज हो चुके थे, जिससे केवल 39 मामले ही प्रभावी बचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इन छोटे–मोटे महामारी–कालीन मुकदमों को खींचने से अदालतों का कीमती समय बर्बाद हो रहा था।

बेंच ने कहा कि इन मुकदमों को जारी रखने से न्याय प्रशासन का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बजाय, इन मामलों को बंद करने से अदालतों को उन गंभीर और जघन्य आपराधिक मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने का मौका मिलेगा, जो लंबे समय से लंबित हैं।

रेलवे को और मजबूत करने की तैयारी: 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान

नई दिल्ली (आभा)। केंद्र सरकार लगातार देश के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारियों में लगी हुई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सरकार ने दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के कुल 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स के तैयार होने के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स को 2029–30 तक पूरा करने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक इस योजना से 17 जिलों के 2, 121 गांवों के करीब 52 लाख स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा माल ढुलाई में भी आसानी होगी।

किन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी–

अराक्कोनम से रेनिगुंटा– इसमें सबसे पहले अराक्कोनम से रेनिगुंटा तक तीसरी और चौथी लाइन का रेलवे लाइन बनाई जानी है। इसकी लंबाई करीब 77 किलोमीटर होगी।

व्हाइटफील्ड से बंगारपेट– दूसरे नंबर पर व्हाइटफील्ड से बंगारपेट तक तीसरी और चौथी लाइन बनाई जानी है। इसकी लंबाई भी करीब 47 किलोमीटर रखी गई है।

होसुर से ओमालपुर– तीसरे नंबर पर होसुर से ओमालुर रूट पर भी रेलवे लाइन का दोहरीकरण किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसकी लंबाई करीब 147 किलोमीटर रखी जाएगी।

?सलेम से करूर और डिंडीगुल– चौथे नंबर पर सलेम से करूर और डिंडीगुल तक भी रेल लाइन के दोहरीकरण की योजना को मंजूरी मिली है। इसकी लंबाई 159 किलोमीटर है।

सिकंदराबाद से काजीपेट– पांचवे नंबर पर सिकंदराबाद (घाटकेसर) से काजीपेट पर मल्टी ट्रैकिंग रेलवे लाइन को बनाए जाने को मंजरी मिली है। इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है।

सपा की सरकार बनने पर होगा व्यापारियों की समस्याओं का समाधान– प्रदीप जायसवाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार कों समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का पी.डी.ए. व्यापारी मण्डलीय सम्मेलन श्याम बाटिका मैरेज लॉन में आयोजित किया गया। व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष रघुनन्दन राम साहु की अध्यक्षता में हुये मण्डलीय सम्मेलन में व्यापारियों के उत्पीड़न, समस्याओं पर विचार के साथ ही भाजपा सरकार के दमनात्मक रवैये की कड़े शव्दों में निन्दा करते हुये वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की मजबूत सरकार बनाने का संकल्प लिया गया।

मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल व्यापारियों के सम्मान, सुरक्षा और हितों के संरक्षण को लेकर संघर्ष के लिए एकजुट होने पर आह्वान किया। कहा कि यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि छोटे, मध्यम और लघु व्यापारियों ने रोजगार सृजन के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बावजूद इसके आज व्यापारी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहा कि महंगाई, बाजार में घटती क्रय शक्ति, ऑनलाइन व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जीएसटी से जुड़ी जटिलताएं, अधिकारियों की अनावश्यक जांच–पड़ताल, बढ़ते व्यावसायिक खर्च और व्यापारियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे गंभीर हैं। इसलिए छोटे व्यापारियों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जिसमें वे बिना भय और अनावश्यक दबाव के अपना व्यापार कर सकें। उन्होने कहा कि सपा की मजबूत सरकार बनने पर ही व्यापारियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा।

–समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के पी.डी.ए. व्यापारी मण्डलीय सम्मेलन में गूंजा व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा

मण्डलीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव, कविन्द्र चौधरी अतुल, पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, सपा नेता दयाशंकर मिश्र आदि ने कहा कि समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों की समस्याओं को केवल मंच तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि व्यापारी हितों की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने पीडीए की विचारधारा के तहत समाज के सभी वर्गों के व्यापारियों को एकजुट होकर सपा को मजबूत करने का आह्वान किया।

समाजवादी पार्टी व्यापार सभा अध्यक्ष रघुनन्दन राम साहु ने कहा कि व्यापारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ–साथ संगठनात्मक रूप से मजबूत होना होगा। जब व्यापारी एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, तभी उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव होगा।

सपा के पीडीए व्यापारी सम्मेलन में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वान्चल प्रभारी विजय जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता के साथ ही संतकबीर नगर जिलाध्यक्ष विजय जायसवाल, सिद्धार्थनगर जिलाध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, सौरभ गुप्ता, रवि गुप्ता, रवि सोनी, राजकुमार श्रीवास्तव, गुरमीत सिंह, इकबाल अहमद, शुभम जायसवाल, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल, शनि गुप्ता, अभय जायसवाल, श्रवण पाण्डेय, राम गोपाल कसौधन, भोला यादव, दीनानाथ साहु, रघुवीर, रजत जायसवाल, संदीप साहू, दिलीप जायसवाल, दिलीप कसौधन, राजेन्द्र जायसवाल, आतमजीत सिंह, योगेश सडाना के साथ ही सिद्धार्थनगर, संतकबीर जनपद के व्यापारी, पदाधिकारी, सपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं को निभानी होगी निर्णायक भूमिका-सुरजीत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। युवा संवाद कार्यक्रम के तहत राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी हर्रैया में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण, संस्कार और सामाजिक दायित्व का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के सह प्रांत प्रचारक सुरजीत ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने की।

मुख्य वक्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण युवाओं के चरित्र, संस्कार और संकल्प से ही संभव है। कहा कि हम सभी युवा खिले हुए पुष्पों की तरह हैं, जिनकी ऊर्जा और क्षमता से राष्ट्र का भविष्य आकार लेता है। युवाओं के जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ समाज और देश के लिए उपयोगी बनना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता ऐसे व्यक्तित्वों के निर्माण की है, जिनके विचारों और कर्मों में राष्ट्र सर्वोपरि हो। युवाओं को भारत को जानें, भारत को मानें, भारत के लिए बनें और भारत के लिए बनाएं के चार सूत्रों को जीवन में आत्मसात करना होगा। भारत की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और जीवन मूल्यों को समझकर ही युवा सशक्त राष्ट्र निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य हमारे संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों ने किया है। भारतीय संस्कृति माता–पिता को देवतुल्य मानने के साथ ही सभी के सुख और कल्याण की कामना करना सिखाती है। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति और पहचान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि आज के दौर में युवाओं के सामने अवसरों के साथ अनेक चुनौतियां भी हैं। ऐसे में संवाद और मार्गदर्शन उन्हें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने तथा सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि युवाओं को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

–युवा संवाद में राष्ट्र, समाज और संस्कृति से जुड़े सवालों पर हुआ सार्थक मंथन

युवा संवाद के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं ने मुख्य वक्ता से राष्ट्र निर्माण, युवाओं के दायित्व, भारतीय संस्कृति, सामाजिक चुनौतियों तथा वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े तमाम प्रश्न पूछे। सुरजीत ने युवाओं के प्रश्नों का सहजता और विस्तार से उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि प्रश्न करना जागरूक युवा की पहचान है और सही दिशा में उठे प्रश्न ही व्यक्ति को बेहतर समझ और समाधान तक पहुंचाते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश की वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन करें और केवल समस्याओं पर चर्चा ही न करें बल्कि उनके समाधान का हिस्सा बनें। भारत को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक जागरूक नागरिक की है। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन विवेक कान्त पाण्डेय ने किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर्रैया के जिला प्रचारक मोहित, गिरजेश, कुलदीप, दीपांशु, मोनू, पंकज सिंह, दिनेश पाण्डेय, प्रभाकर पाण्डेय सहित हजारों की संख्या में छात्र शामिल रहे।

दिशा की बैठक में राहुल गांधी ने सड़कों की खराब दशा की फोटो दिखाई: अधिकारियों से मांगा जबाब

रायबरेली (आभा)। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में क्षेत्र की खराब सड़कों की तस्वीरें दिखाई। गड्ढों वाली सड़कों की फोटो दिखाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा हे। दिशा की बैठक के नामित सदस्य उमेश बहादुर सिंह उर्फ बबलू सिंह ने बताया कि बैठक में राहुल एक अलग अंदाज में नजर आये और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनवायी गयी सड़कों में गड्ढे होने की तस्वीरें दिखायीं।

समाचार एजेंसी को उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि ऐसी सड़कों के नाम गिनाते हुए राहुल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूछा कि आखिर

इन सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं और इन्हें ठीक करने के लिए वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि कौन सी सड़क किस कार्यदायी संस्था ने बनायी है, यह चिह्नित किया जाना चाहिये। सिंह ने बताया कि पीएमजीएसवाई के अधिषासी अभियंता ने बैठक में कहा कि सड़कों के गड्ढों को ठीक कराया जाएगा।

बैठक खत्म होने के बाद सांसद राहुल गांधी बाहर निकले और संवाददाताओं से बिना कुछ कहे चले गए। बैठक में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ रायबरेली को प्राप्त हो रहा है। बैठक में प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने देखी फिल्म 'हनुमान अंश'

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उत्तर प्रदेश (पंजी.) के पदाधिकारियों, व्यापारी साथियों ने बुधवार को जिलाध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में बड़े वन स्थित दर्श सिनेमा पहुंचकर अत्यंत प्रेरणादायक, सांस्कृतिक और धार्मिक सनातन फिल्म 'हनुमान अंश' को सामूहिक रूप से देखा।

जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि यह आयोजन केवल एक चलचित्र देखना मात्र नहीं था, बल्कि सभी के लिए सांस्कृतिक चेतना और अपने गौरवशाली सनातन इतिहास से जुड़ने का एक अत्यंत ही दिव्य अनुभव रहा। हनुमान अंश का संदेश नयी पीढी के लिये उपयोगी है। सभी व्यापारी समयबद्ध तरीके से सिनेमाघर पहुंचे, जिससे इस धार्मिक एवं भव्य आयोजन का पूरी तल्लीनता के साथ आनंद लिया जा सका। दर्श सिनेमा के स्वामी धीरेन्द्र सिंह का लोगों ने आभार व्यक्त किया।

'हनुमान अंश' के दर्शकों में जिला संगठन महामंत्री भारत राम बबलू अग्रहरि, जिला महामंत्री आलोक कुमार

–हनुमान अंश का संदेश नयी पीढी के लिये उपयोगी– राकेश सिंह

दुबे, नगर अध्यक्ष राणा महेंद्र प्रताप, युवा जिला अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव, जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार गुप्ता, नगर संगठन महामंत्री प्रदीप सिंह, नगर महामंत्री धीरेंद्र कुमार सिंह सहित अश्विन कुमार, शुभम कुमार, सुखसागर, सूरज यादव, संजय गुप्ता, अवधेश निषाद, रावेश कुमार श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, कमलेश चौधरी, धर्मेंद्र कुमार यादव, प्रदीप गुप्ता, वीरू साहू, कृष्ण कुमार सिंह, उज्जवल श्रीवास्तव, सूरज कुमार गुप्ता, नितिन श्रीवास्तव, सत्यम सिंह, शिवम सिंह, शुभम गौड़, आकाश सोनी, राजकुमार चौधरी, दीपचंद कसौधन, बृजेश गुप्ता, संत कुमार गुप्ता, सरजू प्रसाद, रवि कुमार, सत्य प्रकाश द्विवेदी, वंदना वर्मा, अमित कुमार चौधरी, अभिषेक कुमार गुप्ता, सुनील कुमार मिश्रा, हिमांशु कसौधन, रामगोपाल सिंह, हेमंत मिश्रा, श्याम श्रीवास्तव और अन्य व्यापारी बंधु शामिल रहे।

संविदा कर्मी का शव मिला: हत्या की आशंका

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के धौमौरा के पास बुधवार सुबह एक युवक का शव मिला। सड़क किनारे शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। वाल्टरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान 26 वर्षीय यशवंत के रूप में हुई है, जो खड़ौवा, थाना नगर का रहने वाला था। यशवंत गोरखपुर नगर निगम में संविदा कर्मी था। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है।

मृतक की बाइक वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से काफी दूर दुबौलिया थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास मिली है। इससे युवक की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि युवक के शव को कहीं और से लाकर धौमौरा के पास फेंका गया है।

शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि युवक आखिरी बार किसके साथ और कहां देखा गया था। उसकी बाइक निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास कैसे पहुंची और युवक की मौत किन हालात में हुई, इन सभी बातों की जांच की जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख रही है। साथ ही, मृतक के मोबाइल फोन की जांच और उसके संपर्क में रहे लोगों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है।

वाल्टरगंज थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार राय ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

रसोईयों ने किया मानदेय बढाने की मांग: सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मिड डे मील रसोइया कर्मचारी यूनियन (सीटू) के बैनर तले बुधवार को रसोइयों ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में रसोइया कर्मचारी न्याय मार्ग स्थित सीटू कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने श्रम संविदा खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मानदेय में की गई बढ़ोतरी काफी नहीं है, इसे न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाना चाहिए। रसोइयों

ने पहले चरण में मनरेगा मजदूरी के बराबर वेतन देने की भी मांग की। इसके अलावा, रसोइयों ने नवीनीकरण में लागू पाल्य व्यवस्था को खत्म करने और कैशलेस इलाज की सुविधा में उन्हें जल्द शामिल करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड केके तिवारी, सहयोगी संगठनों के नेता और बड़ी संख्या में रसोइया कर्मचारी शामिल हुए।

पोषण जागरूकता अभियान में दिया जानकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर ग्रामीण विकास सेवा समिति एवं उत्तर प्रदेश फोर्सेस के संयुक्त तत्वावधान में विकास खण्ड बहादुरपुर के ग्राम सैफाबाद एवं विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम चौकवा में पोषण जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता बैठक आयोजित किया गया।

बैठक के दौरान समुदाय के लोगों को संतुलित एवं विविध आहार, पर्याप्त प्रोटीन, स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा स्वस्थ खान–पान की आदतों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में स्थानीय एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों तथा पैकेज्ड एवं अल्ट्रा–प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बीच अंतर पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को बच्चों के लिए भुना चना, मूंगफली, सत्तू, दलिया, मौसमी फल एवं अन्य स्थानीय पौष्टिक विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने तथा खरीदते समय खाद्य

पदार्थों के लेबल, चीनी, नमक एवं अन्य सामग्री की जानकारी देखने के प्रति भी जागरूक किया गया।

ग्रामीण विकास सेवा समिति के सचिव अम्बुज कुमार यादव ने बताया कि जहाँ एक तरफ सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है वही हम सबका दायित्व है कि इस दिशा में हमें सरकार की नीतियों को शत प्रतिशत सफल बनाने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

लिंक वर्कर स्कीम परियोजना की कलस्टर लिंक वर्कर सोनी ने बताया कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं विकास के लिए स्थानीय, सस्ते और पौष्टिक भोजन को दैनिक आहार का हिस्सा बनाना आवश्यक है। परिवार एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही सुपोषित समाज का निर्माण संभव है।

कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने परिवार में स्वस्थ खान–पान की आदतों को अपनाने तथा बच्चों को पैकेज्ड जंक फूड के स्थान पर स्थानीय पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया।

इस दौरान ग्राम पंचायत की आशा, आगंवाडी, सहायिका एवं ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण विकास सेवा समिति का कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 10 सितम्बर 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

सियासी डिजिटल जंग

समय बदल गया है। अब राजनीतिक दलों में डिजिटल जंग के सिलसिले स्थायी होते जा रहे हैं। जैसे—जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है सोशल मीडिया पर आरोप—प्रत्यारोप, वीडियो वार जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच की चुनावी तनातनी अब केवल राजनैतिक रैलियों या सदन के पटल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह संघर्ष एक बेहद आक्रामक और वर्चुअल जंग का रूप ले चुका है। जैसे—जैसे आगामी विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, दोनों दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक द्वंद के तौर—तरीके भी पूरी तरह बदल चुके हैं। अब मंच के भाषणों से ज्यादा एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होने वाले तीखे वीडियो, मीम्स, एआई जनरेटेड कंटेंट और ताबड़तोड़ बयानों ने मुख्य राजनीतिक युद्धभूमि का स्थान ले लिया है। इस वर्चुअल रणक्षेत्र में दोनों नेता एक—दूसरे की नीतियों, व्यक्तिगत छवि और राजनीतिक अतीत को कटघरे में खड़ा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

ताजा मामलों में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे के दौरान उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति न मिलने पर सियासी आरोप—प्रत्यारोप का दौर गरमा गया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को सत्ताधारी दल की गहरी राजनीतिक बौखलाहट और तानाशाही रवैये का प्रतीक करार दिया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बढ़ते जनाधार से घबराई भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझकर विपक्षी दलों के कार्यक्रमों में प्रशासनिक अड़ंगे लगा रही है, ताकि लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा सके। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति सुरक्षा और ऐनवक्त पर तय किए गए सुरक्षा मानकों के अनुपालन न होने के कारण नहीं दी गई थी। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि विपक्ष हर प्रशासनिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर सनसनी फैलाने की कोशिश करता है और कानून के नियमों से ऊपर उठकर काम करना चाहता है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से राज्य में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल के बीच की राजनीतिक रस्साकशी को और अधिक तीखा बना दिया है, जहां हर छोटी घटना पर दोनों दल एक—दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

प्रदेश की राजनीति में इस हाई—टेक टकराव का सबसे बड़ा और प्रमुख आधार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे बने हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े विषय शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंदिर निर्माण में दान और चढ़ावे में हेराफेरी जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को उठाकर सीधे तौर पर सरकार की पारदर्शिता को कटघरे में खड़ा किया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा खेमे ने भी सोशल मीडिया पर आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर सनातन आस्था को ठेस पहुंचाने और धार्मिक स्थलों की गरिमा को धूमिल करने के षड्यंत्र रचने का करारा आरोप लगाया है। इस वैचारिक और डिजिटल रस्साकशी के दौरान कई बार मामला तब और अधिक बिगड़ जाता है, जब दोनों तरफ से एआई—जनरेटेड वीडियो या डिजिटल कैरिकेचर का इस्तेमाल करके एक—दूसरे के शीर्ष नेतृत्व को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाता है। इस तरह के विजुअल और ऑडियो टूल्स के जरिए जब तीखे व्यंग्य और आरोप प्रसारित किए जाते हैं, तो इंटरनेट पर दोनों दलों के समर्थकों के बीच एक वर्चुअल युद्ध छिड़ जाता है, जो कई बार राजनीतिक मर्यादाओं की सीमा को भी लांघने लगता है।

डिजिटल जंग का दूसरा सबसे बड़ा और धारदार आधार कानून—व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और व्यक्तिगत आक्षेप हैं, जिन्हें दोनों नेता अपनी—अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मुख्य हथियार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर सभा और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सपा के पुराने शासनकाल को गुंडाराज, माफिया राज और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के रूप में चित्रित करते हैं, वहीं वे समाजवादी पार्टी को परिवार का सिंडिकेट करार देते हुए यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस पार्टी की पूरी धुरी केवल एक ही परिवार के इर्द—गिर्द घूमती है। इसके विपरीत, अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार पर तानाशाही, बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और भेदभावपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के गंभीर आरोप मढ़ते हैं। अखिलेश यादव अक्सर मुख्यमंत्री के दौरों, उनके भाषणों के तेवर और प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाते हुए तीखे व्यंग्य भरे पोस्ट करते हैं, जिनका सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता और खुद मुख्यमंत्री आंकड़ों और तीखे बयानों के साथ पलटवार करते हैं।

यह डिजिटल और सियासी द्वंद्व इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले चुनावों में जीत—हार का फैसला केवल रैलियों से नहीं, बल्कि जनमानस की सोच को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करने की क्षमता से भी तय होगा। जब भी सत्ता पक्ष की ओर से कोई विकास परियोजना का उद्घाटन किया जाता है या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लिया जाता है, तो विपक्ष फौरन डिजिटल प्लेटफार्म्स पर उसके दूसरे पहलुओं को उजागर कर देता है, और इसके उलट विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए सत्ताधारी दल का आईटी सेल और वरिष्ठ नेता पूरी मुस्तैदी से मैदान में डटे रहते हैं। इस वर्चुअल संघर्ष ने न केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बेहद व्यक्तिगत और आक्रामक बना दिया है, बल्कि आम जनता और खासतौर पर युवा वर्ग के स्मार्टफोन की स्क्रीन पर हर पल राजनीतिक सरगर्मी को जिंदा रखा है। दोनों ही नेता जनता के बीच यह संदेश देने की होड़ में हैं कि कौन उत्तर प्रदेश के असल मुद्दों का सच्चा हितैषी है और कौन केवल डिजिटल प्रोपेगैंडा में व्यस्त है, जिसके चलते यह चुनावी जंग अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर एक ट्वीट, हर एक वीडियो और हर एक बयान का राजनीतिक नफा—नुकसान बहुत दूर तक असर डालता है।

देश में घूम रहे लाखों दिमागी नफरती 'स्वतंत्र'

—निर्मल रानी—

इन दिनों स्वतंत्र भारद्वाज नामक एक 21 वर्षीय नवयुवक अपने कुछ अति नफरती पॉडकास्ट की वजह से चर्चा में है। मूल रूप से बिहार के दरभंगा के ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा यह नवयुवक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा है। वह खुद को कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़ा हुआ बताता है और कई हिंदू संगठनों और गोरक्षकों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम भी करता रहा है। पिछले दिनों इसने एक यूट्यूब चौनल के पॉडकास्ट में अपना संगीन जुर्म कुबूल करते हुये जो खुलासे किये और जिसतरह नफरत का जहर उगला वह देश के शांतिप्रिय समाज को हैरान करने वाले थे। पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज ने बड़ी ही बेबाकी और गर्व के साथ हंसते हुए यह दावा किया कि उसने जंतर—मंतर पर प्रदर्शन काक्रोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय कुमार का सिर फोड़ दिया था। उसने यह भी कहा कि पीड़ित को गंभीर चोट आई थी और लगभग 60 टांके लगे थे। उसने आगे कहा कि ऐसी चोट पर अमूमन धारा 307 (हाफ मर्डर्ध हत्या का प्रयास) लगती है। फिर उसने बड़ी शान से कहा कि 'बंदा एम्बुलेंस से अस्पताल जा रहा था', लेकिन वह खुद अगले ही दिन बाहर आ गया और उसे एक रात भी जेल में नहीं बितानी पड़ी। इसी पॉडकास्ट में उसने यह दावा भी किया कि पीएम मोदी,बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आदि उसके 'बड़े भाई' जैसे हैं। उसका कहना था कि इन बड़े नेताओं और रसूखदारों के फोन आने पर और उनकी पैरवी के दबाव में दिल्ली पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। उसने पॉडकास्ट में छात्रा व एक्टिविस्ट निशु आजाद को भी धमकाते हुए कहा कि 'अब निशु अगला टारगेट है और सारी फील्डिंग सेट है'। स्वतंत्र भारद्वाज ने इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रति अपनी गहरी नफरत भी जाहिर की थी। उसने कहा कि वह मौका खोजता है कि कोई मुस्लिम गलती करे तो वह उनका ष्इलाजष करे। उसने गोल टोपी और दाढ़ी वाले लोगों को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान भी दिए थे। आज देश की धर्मनिरपेक्षता व संविधान का सम्मान करने वाला देश का एक बड़ा वर्ग भले ही श्स्वतंत्रश की बातों व उसके दुस्साहस का विरोध क्यों न कर रहा हो परन्तु इसके बावजूद भी चंद नफरती दक्षिणपंथी लोगों का समुह उसके समर्थन में भी नजर आया।

इस नफरती जहरीले युवक को कांग्रेस,राहुल गाँधी,काक्रोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं व सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के भारी दबाव व प्रदर्शन के बाद फिलहाल गिरफ्तार किये जाने की खबर है। किसी दक्षिणपंथी व्यक्ति के नफरत और आपराधिक कुबूलनामे का यह पहला वीडिओ नहीं है। याद कीजिये गुजरात दंगों के बारे में साल 2007 में श्तहलकाश पत्रिका के पत्रकार आशीष खेतान द्वारा किए गए श्ऑपरेशन कलंकश नामक स्टिंग ऑपरेशन में, बजरंग दल के तत्कालीन गुजरात प्रमुख बाबू बजरंगी उर्फ बाबूभाई पटेल ने कैमरे पर 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार में अपनी सीधी भूमिका और बेहद खौफनाक अपराधों में अपनी संलिप्तता को इसी तरह कुबूल किया था। बाबू बजरंगी ने बड़ी ही क्रूरता और गर्व के साथ हंसते हुए और छाती ठोककर स्वीकार किया था कि उसने नरोदा पाटिया में लोगों को बेरहमी से काटा और जिंदा जलाया था। उसने कहा था, ष्हमें मारने में बहुत मजा आया... ऐसा लगा जैसे हम महाराणा प्रताप हैं।ष उसने कैमरे पर दावा किया था कि उसने कौसर बानो नामक एक नौ महीने की गर्भवती मुस्लिम महिला के पेट को तलवार से चीर दिया था। उसने बताया था कि कैसे दंगाइयों की भीड़ ने नरोदा पाटिया इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि कोई भी मुस्लिम बचकर भाग न सके। उसने पूरे इलाके को आग के हवाले करने की बात भी स्वीकार की थी। बजरंगी ने कबूल किया था कि गोधरा कांड का बदला लेने के लिए उसने खुद रिवॉल्वर, तलवारें और हथियार बांटे थे। उसने अपनी एक गन फैक्ट्री होने और वहां बड़ी मात्रा में डीजल बम तथा पाइप बम बनाकर हिंदुओं को सप्लाई करने की बात भी कही थी। उसने यह दावा भी किया था कि दंगों के दौरान राज्य की पुलिस मूकदर्शक बनी रही और उनका पूरा साथ दे रही थी। उसने यह भी दावा किया था कि दंगों के बाद जब उसकेखिलाफ मामले दर्ज हुए, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने उसे सुरक्षित जगहों पर छिपने और कानूनी राहत दिलाने में मदद की थी। इसी ऑन—कैमरा कबूलनामे और अन्य चश्मदीदों के बयानों को मुख्य आधार बनाकर ही अदालत ने 2012 में बाबू बजरंगी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। यह और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे मार्च 2019 में खराब स्वास्थ्य और मेडिकल ग्राउंड पर सशर्त जमानत दे दी थी। जेल प्रशासन और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक बाबू बजरंगी की आंखों की रोशनी लगभग 100 प्रतिशत खत्म हो चुकी है और वह पूरी तरह से दृष्टिहीन हो चुका है। साथ ही उसकी बायपास सर्जरी भी हो चुकी है। इसी खराब शारीरिक स्थिति को आधार बनाते हुए अदालत ने उसे मानवीय आधार पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके अलावा साल 2023 में गुजरात दंगों से ही जुड़े नरोदा गाम नरसंहार मामला में भी कोर्ट ने बाबू बजरंगी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। नरोदा पाटिया मामले में उसकी दोष सिद्धि बरकरार है, लेकिन वह जेल से बाहर अपनी जमानत की अवधि पर है।

आज देश की धर्मनिरपेक्षता व संविधान का सम्मान करने वाला देश का एक बड़ा वर्ग भले ही श्स्वतंत्रश की बातों व उसके दुस्साहस का विरोध क्यों न कर रहा हो पांच इसके बावजूद भी चंद लोगों का समुह उसके समर्थन में भी नजर आया। इस 'नफरती गिरोह ' को आखिर खाद पानी कहाँ से मिलता है ? यही वह श्दिमागी नफरती श के संरक्षक हैं जिन्होंने समय समय पर कभी माया कोडनानी को तो कभी बाबू बजरंगी को कभी जयदीप पटेल तो कभी प्रह्लाद गोसा व दयाभाई पटेल जैसे गुजरात दंगों के 67 प्रमुख आरोपी सत्ता के सहारे बचाए गए। यही वह नफरती तंत्र है जिसकी वजह से एहसान जाफरी को जिंदा जला देने वाले बिपिन पटेल और पुलिस निरीक्षक के जी एर्दा आदि सब बाइज्जत बरी हो गए। इसी के द्वारा बेस्ट बेकरी काण्ड में 14 मासूमों को जलाकर खाक कर देने वाले सभी बरी हो गए थे। इसी नफरती तंत्र ने बिल्किस बानो के 11 सजायाफ्ता बलात्कारी रिहा कर दिए थे जिसे भारी जनाक्रोश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जेल भेजा। दरअसल देश की सामाजिक एकता व सद्भाव को तहस नहस करने वाले सत्ता संरक्षित यही भारतीय दक्षिणपंथी हैं। ऐसे हिंसक एजेंडे वाले सभी संगठनों व समूहों को भंग करने और कानून के अनुसार उनपर मुकदमा चलाने की जरूरत है। यदि हम गाँधी के विचारों का भारत चाहते हैं तो हमें अपनी बहुलवादी समन्वयवादी परंपरा पर ऐसे हमलों को शांतिपूर्ण ढंग से नकारने के लिए बौद्धिक रूप से सुसज्जित और नैतिक रूप से तैयार एक नागरिक समाज की आवश्यकता है। और यह एक ऐसा काम है जिसे देश को एकजुट होकर पूरा करना पड़ेगा। छात्रों और युवाओं को अपनी वैचारिक, राजनीतिक प्रवृत्तियों की परवाह किए बिना इस सार्थक अभियान का नेतृत्व करना होगा और वैमनस्यवादियों का जवाब देना होगा। क्योंकि दुर्भाग्यवश ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि आज एक 'स्वतंत्र भारद्वाज' ही नहीं बल्कि देश में लाखों दिमागी नफरती 'स्वतंत्र' घूम रहे हैं।

बीजेपी जिला प्रभारियों को बदलने का दांव

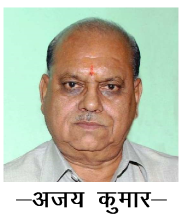

—अजय कुमार—

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी धीरे—धीरे गरमाती जा रही है। राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक तैयारियों के तहत सांगठनिक मशीनरी को मथना शुरू कर दिया है। गौरतलब है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव केवल बयानों और भाषणों से नहीं लड़े जाते, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत, अनुशासित और दुरुस्त संगठन की बड़ी भूमिका होती है। भाजपा इस बात को भली—भांति समझती है कि संगठन के कमजोर होने का मतलब कांग्रेस बन जाना होता है। इसीलिये उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सूबे में तीसरी बार विजय हासिल करने के लिए जमीन पर पार्टी के ढांचे का एकदम सटीक बैठाये जाने के लिये लम्बा विचार—विमर्श चल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश और क्षेत्रीय कार्यकारिणी में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस जिलों के प्रभारियों और जिला कमेटियों को बदलने पर केंद्रित हो गया है। सांगठनिक फेरबदल की इन चल रही बयारों और सुगबुगाहटों ने उन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की नींद उड़ा दी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खुद को टिकट का सबसे प्रबल दावेदार मानकर चल रहे थे।

संगठनात्मक बदलाव के इस सिलसिले की शुरुआत निचले और मध्यम स्तर पर व्यवस्थित ढंग से की जा रही है, जिसके तहत पिछले दिनों मुरादाबाद महानगर और जिला कार्यकारिणी के गठन व पुनर्गठन के जरिए साफ संदेश दे दिया गया था। इन नई कमेटियों के गठन के पीछे केवल सतही बदलाव का उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसके जरिए बहुत ही बारीकी से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत ताने—बाने से गहराई से जुड़ी हुई है और कोई भी दल सामाजिक संतुलन को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता है। भाजपा ने जिस प्रकार से विभिन्न जिलों में नियुक्तियों के दौरान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व किसी भी एक वर्ग या समीकरण के भरोसे चुनाव में उतरने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हर जिले और महानगर में वहां की सामाजिक जनसांख्यिकी के मुताबिक चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि चुनावों से ठीक पहले किसी भी प्रकार के असंतोष को पनपने से रोका जा सके और सभी प्रमुख जातियों को संगठन के साथ जोड़कर एक मजबूत संदेश दिया जा सके।

जिला स्तर पर होने वाले इन बदलावों की श्रृंखला में अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण जिला प्रभारियों का फेरबदल माना जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिला प्रभारी की भूमिका किसी भी जिले में पार्टी के भीतर बेहद प्रभावी और निर्णायक होती है। जिला प्रभारी न केवल संगठन और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय का काम करते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति की रूपरेखा तय करने में भी उनकी केंद्रीय भूमिका होती है। जब किसी जिले का प्रभारी बदला जाता है, तो उस जिले की पूरी राजनीतिक गतिशीलता प्रभावित होती है। अब तक जिन जिलों में पुराने प्रभारी जमे हुए थे, उनके साथ स्थानीय नेताओं और टिकट के दावेदारों के समीकरण सेट हो चुके थे। कई दावेदार पिछले कई वर्षों से अपने आकाओं और प्रभारियों के जरिए जमीन तैयार करने में जुटे थे, ताकि सही समय पर टिकट की जुगत भिड़ाई जा सके। लेकिन नए प्रभारियों के आने की संभावना मात्र से इन पुराने समीकरणों के ध्वस्त होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज होना स्वाभाविक है।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक असर उन नेताओं पर पड़ा है, जो लंबे समय से खुद को क्षेत्र का सर्वसर्वा मानकर बैठे थे और जिन्हें लगता था कि स्थानीय संगठन पर उनकी पकड़ के कारण पार्टी उनके सामने टिकट वितरण में किसी और विकल्प पर विचार ही नहीं करेगी। भाजपा में संगठनात्मक संस्कृति हमेशा से व्यक्ति—केंद्रित न होकर व्यवस्था—केंद्रित रही है, और समय—समय पर प्रभारियों को बदलकर पार्टी यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नेता या पदाधिकारी एक ही जगह पर लंबे समय तक रहकर गुटबाजी या व्यक्तिगत प्रभाव का केंद्र न बन जाए। जब नए जिला प्रभारी आएंगे, तो वे अपने साथ नई कार्यशैली, निष्पक्ष आकलन रिपोर्ट और बिल्कुल नया दृष्टिकोण लेकर आएंगे। वे बिना किसी पूर्व पूर्वाग्रह के जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे कि कौन सा नेता वास्तव में जनता के बीच लोकप्रिय है और किसकी सक्रियता सिर्फ कागजों तक सीमित है। यही वह बात है, जो उन दावेदारों को सबसे ज्यादा डरा रही है, जिनकी पकड़ जनता के बीच कम और पार्टी कार्यालयों के गलियारों में ज्यादा मजबूत मानी जाती है।

टिकट के दावेदारों की बढ़ी हुई मुश्किलों के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि नए प्रभारियों के जरिए पार्टी हाईकमान का सीधा संदेश कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता पर आधारित है। अब तक टिकट के कई दावेदार सिर्फ इस भ्रम में जीते रहे हैं कि उनके पास वित्तीय संसाधन हैं या पार्टी के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से उनकी नजदीकी है, तो टिकट उनकी झोली में खुद—ब—खुद आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने माइक्रो—मैनेजमेंट और जमीनी फीडबैक के आधार पर बदलाव करने शुरू किए हैं, उससे साफ है कि इस बार पैराशूट या केवल सिफारिश के दम पर टिकट पाने की राह आसान नहीं होगी। जिला प्रभारियों के बदलने से स्थानीय स्तर पर चल रहे वे तमाम गुप्त समीकरण और समझौते बिखर जाएंगे, जिनके बूते लोग टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। नए प्रभारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ जिताऊ और जुझारू उम्मीदवारों के पैनल तैयार करें, जिससे उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो सिर्फ हवा हवाई दावों के दम पर अपनी जमीन मजबूत मान रहे थे।

इसके साथ ही, इस पूरी संगठनात्मक सर्जरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव नजदीक आते—आते स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं, जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। नए प्रभारियों की तैनाती इस बात को भी ध्यान में रखकर की जा रही है कि वे समन्वय स्थापित करने में माहिर हों और किसी भी तरह के आंतरिक विरोध या भीतरघात को समय रहते कुचल सकें। जब संगठन का पहिया दुरुस्त होता है और नीचे से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों में एक स्पष्ट वैचारिक व कार्यगत अनुशासन होता है, तो चुनावी प्रबंधन स्वतः आसान हो जाता है। भाजपा का यह आंतरिक फेरबदल इस बात का प्रमाण है कि पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करना शुरू कर दिया है, ताकि चुनावी समर में उतरने से पहले संगठन का हर एक सिपाही पूरी तरह से प्रशिक्षित और युद्ध के लिए तैयार मिले।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्षी दल भी अपनी रणनीतियों को धार देने में लगे हैं, ऐसे में भाजपा का यह मथने वाला अभियान उसकी दूरगामी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। संगठन के भीतर लगातार हो रहे इन परिवर्तनों से भले ही कुछ समय के लिए असंतोष या असमंजस की स्थिति पैदा होती हो, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह पार्टी को अधिक अनुशासित और धारदार बनाता है। जिन दावेदारों की मुश्किलें इन बदलावों की वजह से बढ़ी हैं, उनके पास अब अपनी कार्यशैली बदलने और जनता के बीच अपनी वास्तविक जमीनी पकड़ साबित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब केवल भाई—भतीजावाद या व्यक्तिगत नजदीकियों के सहारे उम्मीदवारी हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए संगठन के मानकों पर खरा उतरना ही होगा। अंततः, उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह दौर इस बात का गवाह बन रहा है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए केवल चेहरों पर नहीं, बल्कि एक अचूक और परिष्कृत सांगठनिक तंत्र के निर्माण पर पूरी ताकत से काम कर रही है, जिसके आगे हर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को किनारे होना पड़ रहा है।

मिट्टी बचेगी, तभी खेती बचेगी

— डॉ. प्रियंका सौरभ—

भारतीय कृषि अब एक नए युग की ओर अग्रसर है, जहाँ विकास का आकलन करने के लिए केवल वृद्धि ही एकमात्र मापदंड नहीं रह गया है। मिट्टी की घटती उर्वरता, भूजल की कमी, जैव विविधता का क्षय, जलवायु परिवर्तनशीलता और बढ़ती खेती लागत के कारण किसान और कृषि क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, पुनर्योजी कृषि एक आशाजनक मार्ग है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा, बल्कि वास्तव में मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता, जल प्रणालियों और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बेहतर बनाकर कृषि उत्पादकता को बनाए रखेगा।

मुख्य बात पुनर्योजी कृषि पर ध्यान केंद्रित करना और कृषि के पारिस्थितिक स्तंभों को पुनर्स्थापित करना है। गहन खेती, रासायनिक इनपुट पर अत्यधिक निर्भरता और एक ही फसल की खेती के कारण पिछले कई दशकों से कुछ क्षेत्रों में पोषक तत्वों का असंतुलन और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई है। पुनर्योजी कृषि वह दृष्टिकोण है जिसमें जीवित मिट्टी कृषि उत्पादन का केंद्र होती है। खाद बनाना, हरी खाद का उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन और जैविक पदार्थों का उपयोग सहित मृदा प्रबंधन, मिट्टी की संरचना, उसकी प्रतिक्रियाशीलता और पोषक तत्व चक्रण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

मिट्टी को ढककर रखने का सिद्धांत एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मिट्टी आसानी से कटाव के कारण नष्ट हो जाती है, और अत्यधिक वाष्पीकरण या तापमान में अचानक बदलाव से भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। मल्चिंग, आवरण फसलें और अवशेषों को मिट्टी में बनाए रखने से मिट्टी की सतह को बनाए रखने और नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। विशेष रूप से वर्षा आधारित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, यह उपयोगी है क्योंकि इससे मिट्टी के स्वास्थ्य और नमी को बनाए रखने में सुधार होता है, जिससे फसलों पर सूखे की अल्पकालिक अवधि का प्रभाव कम हो जाता है। पुनर्योजी कृषि यह भी समझती है कि जैव विविधता कृषि उत्पादकता के लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक संपत्ति है। फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी, मिश्रित खेती और एकीकृत कृषि प्रणालियों को लागू करके अधिक लचीले उत्पादन परिदृश्य विकसित किए जा सकते हैं। फसलों और पशुधन, मत्स्य पालन या वृक्षों के साथ प्रबंधित कृषि भूमि कृषि आय में विविधता लाने और पोषक तत्व चक्रण में सुधार करने में मदद कर सकती है। इस प्रकार की प्रणालियाँ लाभकारी कीटों और अन्य जीवों का समर्थन करने में भी मदद कर सकती हैं, बजाय इसके कि प्रणाली को अधिक कमजोर और कुछ मामलों में बाहरी इनपुट पर निर्भर बना दें।

जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वर्षा का पैटर्न अनियमित होता जा रहा है, लू की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सूखा एवं बाढ़ आम होती जा रही हैं। अनियमित वर्षा, लू, सूखा एवं बाढ़ तथा कीटों की बदलती आबादी भारतीय किसानों के सामने चुनौतियों को बढ़ा रही है। पुनर्योजी पद्धतियों से मृदा में कार्बनिक कार्बन, जल धारण क्षमता और जैविक गतिविधि में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता विकसित करने में मदद मिल सकती है। फसल विविधता से किसी एक फसल को जलवायु परिवर्तन के झटके से होने वाली कुल कृषि आय के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार, एकीकृत कृषि विभिन्न उत्पादन स्रोतों से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों को कम कर सकती है। यह बदलाव जल प्रबंधन का अभिन्न अंग होना चाहिए।

गैरकानूनी हिरासत पर हाई कोर्ट सख्त, 4 फरियादियों को थानेदार की सैलरी से मुआवजा देने का आदेश

संवाददाता–देवरिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के गौरी बाजार थाने में चार याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया। थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग गायब होने और कैमरे खराब होने के पुलिस के दावों पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने एसएचओ और पुलिस अधीक्षक से तीखे सवाल किए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि यदि 14 अप्रैल से कैमरा काम कर रहा था तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां है? अदालत ने एसएचओ से सवाल किया कि वह दो महीने से थाने का प्रभारी था, फिर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां चली गई। एसएचओ ने अदालत को बताया कि 12 अप्रैल 2026 को सीसीटीवी व्यवस्था में खराबी आ गई थी। अदालत ने पूछा कि व्यवस्था की मरम्मत को लेकर सामान्य डायरी (जीडी) में कोई प्रविष्टि की गई थी या नहीं। एसएचओ ने कहा कि ऐसी कोई जीडी प्रविष्टि नहीं की गई। इस पर अदालत ने पुलिस के स्पष्टीकरण पर गंभीर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मौखिक टिप्पणी करते हुए अधिकारियों को झूठ बोलने वालों का झुंड तक कह दिया।

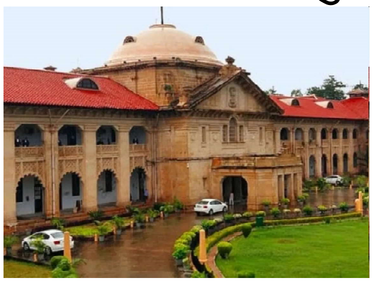

सुनवाई के दौरान देवरिया के एसपी ने अदालत से माफी मांगी। इस पर न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा, “अदालत से माफी मत मांगिए, जनता से माफी मांगिए।” पीठ ने एसपी से यह भी पूछा कि सीसीटीवी व्यवस्था में लापरवाही के लिए एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने सवाल किया कि क्या एसएचओ को निलंबित किया गया या सेवा से बर्खास्त किया गया। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने टिप्पणी की कि थाने का एसएचओ अगर जीडी में जांच तक नहीं कर सकता तो उसे सेवा में नहीं रहना चाहिए। अदालत ने यहां तक कहा कि ऐसा अधिकारी सिपाही बनने के भी योग्य नहीं है। एसपी ने बताया कि एसएचओ को अपराध शाखा भेज दिया गया है। हालांकि, अदालत इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुई। मामला चार लोगों की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है। आरोप है कि चारों को देवरिया के गौरी बाजार थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। इनमें कुछ याचिकाकर्ताओं को करीब 10 दिन तक और अन्य को अलग–अलग अवधि तक हिरासत में रखे जाने का आरोप है। बताया गया कि कथित हिरासत का समय 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 के बीच का है। अदालत ने पहले थाने के अंदर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पेश करने का आदेश दिया था, ताकि याचिका में लगाए गए आरोपों की सच्चाई की जांच की जा सके।

दो सितंबर को राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि कथित घटना से पहले थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग व्यवस्था में खराबी थी। इसके बाद अदालत ने देवरिया के एसपी और संबंधित एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। बुधवार की सुनवाई में अदालत ने एसपी से भी पूछा कि उन्हें थाने की सीसीटीवी व्यवस्था खराब होने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। एसपी ने कहा कि उन्हें इसकी सूचना नहीं थी। अदालत ने पूछा कि यदि एसएचओ की गलती सामने आई थी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीठ ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताई। अदालत ने देवरिया जिले के थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए जारी की गई रकम को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत के सामने बताया गया कि सीसीटीवी व्यवस्था के लिए 46.46 लाख रुपये जारी किए गए थे। अदालत ने सवाल किया कि जब सीसीटीवी का काम पूरा नहीं हुआ था तो संबंधित एजेंसी को पूरी रकम क्यों जारी कर दी गई? पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एजेंसी को काली सूची में डालने के बजाय पूरी रकम जारी कर दी गई और केवल आश्वासन के आधार पर भुगतान कर दिया गया। अदालत ने अपने पहले के आदेश में भी इस बात पर सवाल उठाया था कि सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने कार्रवाई तब शुरू की, जब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। दो सितंबर के आदेश में अदालत ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि जिला अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने और चार अगस्त के आदेश के बाद ही कार्रवाई शुरू की। अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि सीसीटीवी व्यवस्था के लिए जारी धनराशि की तारीख तक हलफनामे में स्पष्ट नहीं की गई। पीठ ने इसे महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी बताया था।

हाईकोर्ट ने चारों याचिकाकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता संख्या दो, तीन और चार को 20–20 हजार रुपये तथा याचिकाकर्ता संख्या एक को पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस तरह कुल 65 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह है कि अदालत ने निर्देश दिया कि यह रकम संबंधित एसएचओ के वेतन से वसूल की जाए। आगे से खबर तैयार करते समय इसी पूरी तरह हिंदी लिपि वाले प्रारूप को प्राथमिकता दूंगा। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाने में चार याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों से कड़े सवाल किए। अदालत ने थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने पर नाराजगी जताते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एसपी देवरिया और थाना प्रभारी एसएचओ से जवाब मांगा।

दो सितंबर की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कथित घटना से पहले कुछ दिनों तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सिस्टम में खराबी थी। इसके बाद अदालत ने एसपी देवरिया और संबंधित एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। बुधवार की सुनवाई में अदालत ने एसएचओ से सीसीटीवी फुटेज गायब होने को लेकर कई सवाल किए। कोर्ट ने पूछा, “अगर कैमरा 14 अप्रैल से काम कर रहा था तो रिकॉर्डिंग कहां है? आप दो महीने तक एसएचओ रहे। रिकॉर्डिंग कहां है? एसएचओ ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी सिस्टम में 12 अप्रैल 2026 को खराबी आ गई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि सीसीटीवी की मरम्मत को लेकर जनरल डायरी (जीडी) में कोई प्रविष्टि की गई थी या नहीं। एसएचओ ने बताया कि ऐसी कोई जीडी एंट्री नहीं की गई थी। सुनवाई के दौरान एसपी देवरिया से भी सवाल किए गए। एसपी ने बताया कि उन्हें सीसीटीवी सिस्टम के काम नहीं करने की जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने पूछा कि सीसीटीवी में हुई लापरवाही के लिए एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

किसानों की मांगों को लेकर धरना, भारतीय किसान संघ नें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

संवाददाता–बहराइच। किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश ने बुधवार को फखरपुर विकासखंड परिसर में एक दिवसीय धरना–प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 3 बजे संघ के पदाधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई।

किसान संघ ने मांग की कि राज्य सरकार किसान सम्मान निधि में केंद्र की तरह हर साल छह हजार रुपए का अपना हिस्सा दे। इससे किसानों को कुल 12 हजार रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिल सकेगी। किसानों की पूरी उपज एमएसपी पर खरीदने के लिए कानून बनाने और सभी खरीद केंद्रों को सरकारी या व्यापारिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की भी मांग की गई।

ज्ञापन में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 500 रुपए प्रति क्विंटल करने को प्रमुख मांग बनाया गया। किसानों के निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन पूरी तरह मुफ्त करने और भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग भी की गई।

संघ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में किसानों को बाजार भाव का पांच गुना मुआवजा देने के बाद ही जमीन ली जाए। सड़क, रेल समेत अन्य परियोजनाओं के निर्माण के दौरान खेतों तक पहुंच बनी रहे, इसके लिए हर दो किलोमीटर पर बाईपास, अंडरपास और संपर्क मार्ग बनाने की भी मांग की गई।

नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–श्रावस्ती। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को सिरसिया पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के दो दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार शाम करीब 5 बजे गिरफ्तारी की जानकारी दी। आरोपी को तालबघौड़ा से छोटकी सुईया जाने वाले मार्ग के पास से पकड़ा गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर जिले में अपराध और महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सिरसिया पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। थानाध्यक्ष सौरभ सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनोज कुमार और पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तालबघौड़ा से छोटकी सुईया जाने वाले मार्ग के पास घेराबंदी की। पुलिस ने मौके से नसरुद्दीन पुत्र जाबिर खान को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, 7 सितंबर 2026 को पीड़िता के पिता ने सिरसिया थाने में शिकायत दी थी। आरोप था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि 25 अगस्त 2026 को आरोपी ने लड़की को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में सिरसिया थाने में मुकदमा संख्या 250/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस ने इसमें भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई हैं। केस दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बुधवार को मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नसरुद्दीन पुत्र जाबिर खान, निवासी हेमपुर बढ़रहवा, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट भेज दिया।

प्रधानों ने बीडीओ का दफ्तर घेरा, कमरे में किया बंद, कमीशन मांगने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप

संवाददाता–महराजगंज। पनियरा में बुधवार शाम करीब 4 बजे ग्राम प्रधानों ने बीडीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रधानों ने बीडीओ अमिय कुमार शशि पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कमीशन मांगने और ग्राम प्रधानों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विरोध के दौरान प्रधानों ने बीडीओ को उनके कमरे में बंद कर दिया।

प्रधानों का आरोप है कि विकास कार्यों के लिए उनसे गलत तरीके से कमीशन मांगा जाता है। उनका कहना है कि कमीशन नहीं देने पर विकास कार्यों में अड़चन डाली जाती है। विरोध करने पर उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है।

प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश सिंह के नेतृत्व में कई प्रधान ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद बीडीओ के कार्यालय का घेराव किया गया।

विरोध के दौरान प्रधानों ने बीडीओ अमिय कुमार शशि को उनके ही दफ्तर के कमरे में बंद कर दिया। प्रधानों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिले के किसी जिम्मेदार बड़े अधिकारी को मौके पर आकर उनकी बात सुननी चाहिए।

साथ ही कार्रवाई का भरोसा मिलने तक विरोध जारी रखने की बात कही। प्रधानों के विरोध के कुछ समय बाद बीडीओ को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। इसके बावजूद ब्लॉक परिसर में तनाव बना रहा।

बुधवार शाम करीब 6 बजे तक प्रधान ब्लॉक परिसर में मौजूद रहे। उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई। वे मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

देवी पाटन मंडल के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, बनेंगी 43 सड़कें और 12 पुल

संवाददाता–गोण्डा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने देवीपाटन मंडल के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। गोंडा, बलरामपुर बहराइच समेत मंडल के चारों जिलों में लोक निर्माण विभाग की कई कार्ययोजनाओं को शासन ने वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। मंडल की 43 सड़कें चकाचक होंगी। इसके साथ ही देवीपाटन मंडल में 12 लघु पुल व बॉक्स कलवर्ट निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है।

शासन से बजट जारी होने के बाद मंडल में 10.10 किलोमीटर लंबी 13 सड़कों पर लगभग 5.85 करोड़ रुपये से पुनर्निर्माण होगा। अब इन मार्गों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क बेहतर होगा और कृषि कारोबार को रफ्तार मिलेगी। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता योगेन्द्र सिंह ने बताया कि शासन ने मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द सभी सड़कों को निर्माण शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जिले की 30 ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प की राह खुल गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बीते दिनों 57.98 करोड़ की लागत से स्वीकृत इन सड़कों के लिए शासन से पहली किस्त के रूप में 19.47 करोड़ रुपये जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ निर्माण शुरू होगा। सदर, मनकापुर और गौरा में छह–छह, जबकि कटरा, तरबगंज और करनैलगंज में चार–चार सड़कों का निर्माण होगा।

इनमें करनैलगंज विस क्षेत्र में दुल्लापुर–डीहा मार्ग पर 342.09 लाख रुपये और तरबगंज विस क्षेत्र में कादीपुर–चंदाकोट मार्ग पर 317.04 लाख रुपये की लागत आएगी। शासन की ओर से स्वीकृत सड़कों में मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में गोपालपुर–छुटकापुरवा से कुलीबनकट सम्पर्क मार्ग 1.10 किमी का निर्माण 67.67 लाख रुपये की लागत से होगा। सोठिया से सुमेरपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर 25.19 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा करनैलगंज में सहजौरा मंगुरा से डोमाकल्पी शुक्लापुरवा सम्पर्क मार्ग 25.29 लाख रुपये से संवारा जाएगा। वहीं मंडल के अन्य विधानसभा क्षेत्रों उतरौला, बलरामपुर, तुलसीपुर और गैसड़ी क्षेत्र की 10 अन्य सम्पर्क मार्गों का भी कायाकल्प होगा। उतरौला इलाके में हुसैनाबाद रामदीन इण्टर कॉलेज से मधुपुर, बलरामपुर में मुड़ाडीह से गुजरपुरवा और तुलसीपुर जरवा से लोकी खुर्द तक के मार्ग प्रमुख हैं। स्वीकृत सड़कों पर काम शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क और भी बेहतर होगा और किसानों को अपनी उपज (फल, सब्जी, अनाज) मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। बभनजोत क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का सड़क का भी कायाकल्प होगा। देवीपाटन मंडल में 12 लघु सेतु व बॉक्स कलवर्ट निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है। कुल लागत 23.88 करोड़ है, इस पर चालू वित्तीय वर्ष में 4.77 करोड़ जारी कर दिए गए है। इसमें गोंडा को सर्वाधिक पांच पुल मिले हैं, जिन पर 10.58 करोड़ खर्च होंगे। मरचौर–गजसिंह व अल्लीपुर गोकुला में सोतिया नाले, चयपुरवा मार्ग पर टेढ़ी नदी, तुरकोली–धुसवा में नकहा व खड़ौवा में नरवा नाले पर पुल बनेंगे। बहराइच में 10.27 करोड़ से तीन व बलरामपुर में 4.71 करोड़ से चार कलवर्ट का निर्माण होगा।

लापता छात्र का शव रोहिन नदी से मिला

संवाददाता–महराजगंज। त्रिमुहानी पुल से लापता कक्षा सात के छात्र हिमांशु यादव का शव बुधवार को पनियरा थाना क्षेत्र के जर्दी ग्राम पंचायत के भगड़ा टोला स्थित रोहिन नदी में उतराता मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान हिमांशु के रूप में की। छात्र की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। हिमांशु कुछ दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा।

परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। इसी दौरान सदर कोतवाली क्षेत्र में त्रिमुहानी पुल के पास उसकी साइकिल और स्कूल बैग मिले थे। सामान मिलने के बाद परिजनों और पुलिस को आशंका हुई कि छात्र ने रोहिन नदी में छलांग लगा दी होगी। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने नदी में छात्र की तलाश शुरू कर दी थी। बुधवार को भगड़ा टोला के पास रोहिन नदी में लोगों ने एक शव देखा। सूचना पर पनियरा पुलिस मौके पर पहुंची और सदर कोतवाली पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान हिमांशु यादव के रूप में की।

हिमांशु के घर नहीं लौटने के बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिमुहानी पुल के पास उसकी साइकिल और स्कूल बैग मिलने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया था। सामान नदी के पास मिलने के कारण परिजनों और पुलिस को छात्र के नदी में जाने की आशंका हुई थी। इसके बाद रोहिन नदी में लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। बुधवार को जर्दी ग्राम पंचायत के भगड़ा टोला के पास रोहिन नदी में लोगों की नजर एक शव पर पड़ी। सूचना मिलते ही पनियरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और उसकी पहचान कराने के लिए परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे हिमांशु के परिजनों ने शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की। पनियरा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

हिमांशु का शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, घर में मातम छा गया। जिस छात्र की कई दिनों से तलाश की जा रही थी, उसका शव नदी में मिलने से परिवार के लोग सदमे में हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर छात्र की मौत से जुड़े हालात स्पष्ट करने में जुटी है।

मानव तस्करी और बाल अपराधों को लेकर हुई बैठक

संवाददाता–बलरामपुर। पुलिस मानव तस्करी, बाल अपराध और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार, 9 सितंबर 2026 को पुलिस कार्यालय के सभागार में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटी) और विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की मासिक समन्वय गोष्ठी और कार्यशाला हुई। यह गोष्ठी पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल) एएचटी/एसजेपीयू विशाल पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार, महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को असरदार बनाने के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई। अधिकारियों ने जोर दिया कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। कार्यशाला में संबंधित विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों व प्रतिनिधियों को मौजूदा नियमों, कानूनों, सरकारी आदेशों और माननीय न्यायालय के अहम फैसलों की जानकारी दी गई। इनके सही पालन के लिए जरूरी दिशा–निर्देश भी दिए गए। इस गोष्ठी में स्वास्थ्य विभाग, अभियोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग, एसएसबी, समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम विभाग, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), आरपीएफ, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन और कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही जिले के सभी थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और मिशन शक्ति प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया।

राष्ट्रीय पोषण माह शुरूः आंगनबाड़ी से घर–घर पहुंचेगा पोषण का संदेश

संवाददाता–श्रावस्ती। बुधवार को 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के ‘सुपोषित भारत’ के लक्ष्य और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह अभियान कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू किया गया। बुधवार को प्रशासन ने 4:00 बजे बताया कि जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली के जरिए लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी मकसद से हर साल सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इस साल अभियान की थीम ‘हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ रखी गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण जागरूकता का मुख्य केंद्र बनाया जाए। इससे परिवारों और समुदाय को अभियान से जोड़ा जा सकेगा, ताकि इसका फायदा जरूरतमंदों तक अच्छे से पहुंच सके। इस अभियान में छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरी लड़कियों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए अभियान चलाकर ‘सैम’ और ‘मैम’ श्रेणी के बच्चों की पहचान की जाएगी। पहचान किए गए बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए जरूरी कोशिशें की जाएंगी। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत गांव–गांव और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम होंगे। लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार की अहमियत बताई जाएगी। साथ ही पोषण सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार भी बांटा जाएगा। बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए योग और आयुष से जुड़े सेशन भी आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर लोगों का अभियान बनाया जाए। तभी जिले में कुपोषण की समस्या पर अच्छे से काबू पाया जा सकेगा।

तारबंदी में मौत का फंदा! खेत में फंसकर हिरण की दर्दनाक मौत, घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश

संवाददाता–गोण्डा। भरत लाल त्रिपाठी,गोंडारू मनकापुर तहसील क्षेत्र के नरायनपुर ग्रंट गांव में खेतों की सुरक्षा के नाम पर की गई तारबंदी वन्यजीवों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। टिकरी वन रेंज के पुरबिहन टोला के पास एक खेत की तारबंदी में फंसकर एक हिरण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत की तारबंदी में सीधे बिजली का करंट प्रवाहित किया गया था, जिसकी चपेट में आने से हिरण की मौत हुई।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हिरण की मौत बिजली के करंट से हुई अथवा तारबंदी में फंसने के बाद दम घुटने से उसकी जान गई। ग्रामीणों द्वारा खेत मालिक सुशील मौर्या पर तारों में करंट छोड़ने की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वन विभाग यह भी जांच कर रहा है कि खेत में अवैध रूप से विद्युत करंट प्रवाहित किया गया था अथवा वन्यजीवों को रोकने के लिए किसी झटका मशीन का इस्तेमाल किया गया था।

टिकरी रेंज के रेंजर अभिषेक प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वन कर्मियों को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। हिरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यदि हिरण की मौत विद्युत करंट से होने की पुष्टि होती है तो वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

428 वीएचएसएनडी सत्रों का निरीक्षण, सीएचओ अर्चना भारती मिलीं अनुपस्थित, 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश

संवाददाता–देवरिया। बुधवार को 428 वीएचएसएनडी सत्रों का निरीक्षण किया गया। सीएमओ, एसीएमओ, डिप्टी सीएमओ और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने सत्रों का जायजा लिया। इस दौरान टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की गई। रामपुर कारखाना के गौरा में सीएचओ अनुपस्थित मिलीं। सीएमओ ने उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बुधवार दोपहर 12 बजे रामपुर कारखाना ब्लॉक के गौरा स्थित वीएचएसएनडी सत्र का निरीक्षण किया। वहां एएनएम मौजूद थीं। सीएचओ अर्चना भारती नहीं मिलीं।

इस पर सीएमओ ने उनका एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। सत्र में एएनएम ने सात बच्चों और दो गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए थे। सीएमओ ने एएनएम को सभी गर्भवती महिलाओं का ई–कवच पोर्टल पर पूरा पंजीकरण करने को कहा। बच्चों के एमसीपी कार्ड भी पूरी तरह भरने के निर्देश दिए। निरीक्षण में सत्र पर जरूरी सामान मौजूद मिला। हीमोग्लोबिन मीटर भी काम कर रहा था। अधिकारियों ने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की पहचान करने के निर्देश दिए। ऐसी महिलाओं को समय पर सही इलाज दिलाने को कहा गया। सीएमओ ने कहा कि टीकाकरण सत्रों पर आने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉ. एसके सिन्हा ने रुद्रपुर क्षेत्र के सत्रों का निरीक्षण किया। डीटीओ डॉ. राजेश कुमार ने भटनी क्षेत्र में जांच की। डिप्टी सीएमओ डॉ. कार्तिक पांडेय ने रामपुर कारखाना क्षेत्र का जायजा लिया। डिप्टी सीएमओ डॉ. हरेंद्र कुमार और डॉ. आरपी यादव ने भलुअनी क्षेत्र में निरीक्षण किया। डिप्टी सीएमओ डॉ. अश्वनी पांडेय ने शहरी क्षेत्र के सत्र देखे। डिप्टी डीआईओ डॉ. विपिन रंजन ने तरकुलवा ब्लॉक के टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने सत्रों पर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जहां कमियां मिलीं, वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। यूपीटीएसयू, सीफार, जेएसआई और पीसीआई के जिला प्रतिनिधियों ने भी अलग–अलग सत्रों पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग किया।

नगर निगम की बैठक शुरू होते ही हंगामा, सेल्फी प्वाइंट से लेकर राप्ती तट के काम पर भिड़े पार्षद

संवाददाता–गोरखपुर। जिले में नगर निगम बोर्ड की 22वीं बैठक बुधवार को नगर निगम सदन हॉल में सुबह 11ः45 बजे शुरू होते ही हंगामे में बदल गई। विभिन्न वार्डों में कार्यों के प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए। पिंटू गोंड, अजय ओझा और विश्वजीत त्रिपाठी ने आपत्ति जताई कि प्रस्ताव के बारे में सभी पार्षदों को जानकारी क्यों नहीं दी गई। पार्षद राजेंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम निधि के अलावा उनके वार्ड में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि आईजीआरएस पर आई शिकायत के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऋषि मोहन ने प्रस्ताव पर सुझाव देने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ गया। इसके बाद रंजय सिंह जुगनू और विश्वजीत त्रिपाठी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आदर्श वार्ड में सेल्फी प्वाइंट बनाने के प्रस्ताव पर विश्वजीत त्रिपाठी ने सवाल उठाया कि यह सुविधा सिर्फ आदर्श वार्ड में क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने सभी 80 वार्डों में सेल्फी प्वाइंट बनाने की मांग की। पार्षद धर्मदेव चौहान ने भी विरोध किया। करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा। नगर आयुक्त अजय जैन ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव आदर्श नगर के लिए तैयार किया गया है और 10 लाख रुपये की सीमा के भीतर कम बजट में इसे बनाने की योजना है। पार्षद विक्की मिश्रा ने कहा कि उनके वार्ड में भी जगह है, वहां सेल्फी प्वाइंट बनाया जाए।

ओटीएस योजना पर भी चर्चा हुई। पार्षदों से लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। नगर आयुक्त ने कहा कि टैक्स से संबंधित शिकायतों का 15 दिन में निस्तारण किया जाएगा। लोगों से मोबाइल और लैपटॉप लेकर शिविर में पहुंचकर अपनी आपत्तियों का समाधान कराने को कहा गया। राजघाट अंत्येष्टि स्थल को लेकर भी पार्षदों ने सवाल उठाए। पार्षद पवन सिंह ने रसीद की राशि 200 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने की मांग की। विश्वजीत त्रिपाठी ने भी इसका समर्थन किया। पार्षद विक्की मिश्रा ने राशि 50 रुपये करने की मांग रखी। पार्षद शिवेंद्र मिश्र ने अंत्येष्टि स्थल पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। पार्षद जियाउल इस्लाम ने पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि नहीं होने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद भाजपा और सपा पार्षद आमने–सामने आ गए। दोनों पक्षों के पार्षद हंगामा करते हुए मंच तक पहुंच गए। सपा पार्षदों ने कहा कि सदन केवल भाजपा पार्षदों से नहीं चलेगा, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए।

राप्ती तट पर हाईमास्ट घटना के मुद्दे को उठाते हुए विश्वजीत त्रिपाठी ने नगर निगम में बैनर–पोस्टर लगाने की बात कही। उन्होंने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर जर्जर पिलर की मरम्मत कराने की मांग की। इस पर पार्षद विजेंद्र अग्रहरि ने विरोध किया और दोनों के बीच हंगामा शुरू हो गया। पार्षद ऋषि मोहन ने सिंचाई विभाग के कार्यों को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। जियाउल इस्लाम ने कहा कि भाजपा पार्षदों ने कम से कम राप्ती तट के कार्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, इसके लिए उन्हें बधाई। अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव ने विजय चौक नाले से जुड़े प्रस्ताव पर बताया कि नाले की सफाई के दौरान सामने आया कि उसके ऊपर दो मकान बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1967 में नाले की जमीन किराये पर दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इसे गलत बताया गया है। अब मकानों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विकसित भारत क्विज में युवाओं को मिलेगा प्रधानमंत्री के समक्ष विचार रखने का अवसर–अंशिका सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जनपद के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से 'विकसित भारत क्विज' अभियान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह करते हुये मेरा युवा भारत की जिला युवा अधिकारी अंशिका सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चयनित युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और रचनात्मक सोच के जरिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है।

अभियान की पहली कड़ी के रूप में 'विकसित भारत क्विज' का आयोजन माई भारत पोर्टल पर किया जा रहा है। क्विज 22 भाषाओं में होगा। इसमें भारत, भारतीय विरासत, देश की उपलब्धियों, विकास यात्रा और 'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। बताया कि चयन प्रक्रिया कुल पांच चरणों में पूरी होगी। पहला चरण क्विज का है, जो 17 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण में 5 से 9 अक्टूबर तक निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। तीसरे चरण में 10 से 16 नवंबर 2026 के बीच जिला स्तर की चौपियनशिप आयोजित की जाएगी। चौथे चरण में 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक राज्य स्तर पर, इसके बाद पांचवां और अंतिम चरण 10 से 12 जनवरी 2027 तक राष्ट्रीय संवाद के रूप में आयोजित किया जाएगा। अंशिका सिंह ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय संवाद होगा। इसमें चयनित युवाओं को अपने विचार, विजन और सुझाव सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

चौलेंज ट्रैक के तहत युवाओं से भविष्य के शासन–प्रशासन, शहरी बदलाव, जलवायु सुरक्षा, सीमावर्ती एवं पर्वतीय विकास, जनसांख्यिकीय लाभांश, सतत औद्योगीकरण, सांस्कृतिक नेतृत्व, विनिर्माण एवं उद्यमिता, जनजातीय नेतृत्व, नवाचार, अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन, तकनीक एवं रोजगार सृजन तथा ब्लू इकोनॉमी जैसे विषयों पर विचार लिए जाएंगे।

सरयू में नहाने गए दादा–नाती डूबे

संवाददाता–अयोध्या। अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र में सरयू नदी में बुधवार दोपहर भैंस नहलाने गए दादा और नाती गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। हादसे की जानकारी होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश कराई जा रही है, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका। रुदौली क्षेत्र के तराई गांव पसैया के सामने बंधे के पास बुधवार दोपहर करीब दो बजे जगराम(60) अपने नाती शिवा पुत्र भाईलाल(22) के साथ सरयू नदी में भैंस नहलाने गए थे। दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर घटना की जानकारी दी।

स्कूल का ताला तोड़कर एलपीजी सिलेंडर और बर्तन उठा ले गये चोर

संवाददाता–अयोध्या। राम नगरी में चोरों का कहर इन दिनों प्राइमरी स्कूलों पर है। अराजक हो चुके चोर शिक्षकों का सिरदर्द बन गये है। यह स्कूलों में ताला तोड़कर एलपीजी सिलेंडर और बर्तन गायब कर दे रहे हैं, जिससे बच्चों को भोजन से वंचित होना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह थाना महाराजगंज के मया बाजार दलपतपुर रोड पर प्राइमरी पाठशाला में चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चुराया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। गांव के प्रधान व अन्य जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब सरकारी स्कूल के टीचर्स सबसे ज्यादा परेशानी चोरी के कारण बढ़ रही है।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
अदालत– श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–250/98
पुद्दन
बनाम
राम उजागिर आदि
3/1 शोभा देवी पत्नी रामराज 3/2 दुर्गा प्रसाद 3/3 रामजनम पुत्रगण रामराज साकिनान चुरिहारपुर तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 19–10–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 19 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 2026 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
कायमी वाद सं0– 153/2026
केशवराम
बनाम
रामसहाय आदि

1. रामसहाय तथा कथित पुत्र सीताराम उम्र लगभग 50 साल साकिन कलवारी एहतमाली तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 2. कमला पुत्र मटटर उम्र लगभग 50 साल साकिन बलया जगदीशपुर न्याय पंचायत बलया जगदीशपुर तहसील टांडा जिला अम्बेडकरनगर हाल मुकाम कलवारी एहतमाली तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 3. धुपचन्द्र उम्र लगभग 35 साल 4. चन्द्रशेखर उम्र लगभग 32 साल 5. फूलचन्द्र उम्र लगभग 28 साल 6. दिलीप उम्र लगभग 26 साल पुत्रगण रामपलट 7. सुगापती उम्र 65 साल बेवा रामपलट निवासीगण मौजा कलवारी एहतमाली तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 16–09–2026

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 16 माह 09 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

स्कूल बैंड प्रतियोगिता में झिनकू लाल, जीजीआईसी की टीम रही अव्वल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। राजकीय इंटर कॉलेज के बहुउद्देशीय हाल में बुधवार को जनपद स्तरीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैंड की जोशीली धुनों के बीच विद्यार्थियों ने अनुशासन, तालमेल, टीम भावना और वादन कौशल का शानदार प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरीं। बालक एवं बालिका वर्ग में कुल चार विद्यालयों की बैंड पार्टियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजगवा जंगल के पूर्व प्रधानाचार्य सुरेश चंद वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन–अर्चन कर किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि संगीत विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और टीम भावना विकसित करने के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम है। स्कूल बैंड जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करती हैं। आयोजक विद्यालय के प्रवक्ता चंद्रभान पांडेय ने प्रतिभागी विद्यालयों से आए विद्यार्थियों, निर्णायकों एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का स्वागत किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए आयोजन में सहयोग के लिए आभार जताया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रधानाचार्य इंद्र बहादुर, प्रधानाचार्य उदयभान सिंह और प्रधानाचार्य रामचंद्र यादव शामिल रहे। निर्णायकों ने बैंड पार्टियों की प्रस्तुति, अनुशासन, तालमेल, वाद्य यंत्रों के संचालन और समग्र प्रदर्शन के विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया। बालक वर्ग में झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौरी इंटर कॉलेज, कलवारी की बैंड पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती की टीम द्वितीय स्थान पर रही। वहीं बालिका वर्ग में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बस्ती की बैंड पार्टी ने उत्कृष्ट प्रस्तुति के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज, बस्ती की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन मंडलीय सचिव अमित कुमार यादव, प्रभाकर ओझा, माता प्रसाद त्रिपाठी, रमेश चंद्र गुप्ता और विवेक कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न हुआ। आयोजन के संचालन में शारीरिक शिक्षा शिक्षक अजय कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समापन अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर अभ्यास और ऐसे आयोजनों में बढ़–चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया।

नकली बीज से 50 एकड़ फसल बर्बाद किसानों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

संवाददाता–संतकबीरनगर। खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के गजपुर गांव में नकली बीज से करीब 50 एकड़ फसल खराब होने का मामला सामने आया है। फसल बर्बाद होने से नाराज दर्जनों किसानों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने पास के बीज विक्रेताओं से खेती के लिए बीज खरीदे थे। बुवाई के बाद फसल में उम्मीद के मुताबिक बढ़वारी और उत्पादन नहीं हुआ। किसानों के अनुसार, देखते ही देखते करीब 50 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।

रामकृपाल सिंह और किसान दीपचंद ने बताया कि फसल खराब होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत की थी। किसानों का आरोप है कि शिकायत के बाद कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों और बीज निरीक्षक ने मौके पर जांच की, लेकिन निष्पक्ष जांच करने के बजाय गलत रिपोर्ट लगा दी गई।

किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, संबंधित बीज के नमूने की गुणवत्ता की जांच हो और अगर बीज मानकों के खिलाफ पाया जाता है, तो विक्रेता पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसानों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच और फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

किसानों का कहना है कि खेती में लगाई गई उनकी पूरी मेहनत और पूंजी बर्बाद हो गई है। अगर समय पर मामले की जांच कर किसानों को राहत नहीं मिली, तो उनका आर्थिक संकट और गहरा सकता है। इस मौके पर श्यामलाल पासवान, दीपचंद पासवान, ब्रह्मदेव सिंह, राहुल सिंह, मुराली सिंह, मनोज सिंह, सत्येंद्र सिंह, अजय सिंह, हिरालाल, मल्लू सिंह, कन्हई सिंह, आकाश सिंह, श्रीराम, गोविंद सिंह, राजकुमार, चंदन समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे।

बिना काम कराए 5.46 लाख का दिखाया भुगतान ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने का आदेश

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। बर्डपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली में बिना काम कराए 5 लाख 46 हजार 142 रुपये खर्च करने का मामला सामने आया है। डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सचिव केशभान यादव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद सरकारी धन के भुगतान की पूरी प्रक्रिया अब जांच के घेरे में आ गई है। यह मामला ककरहवा हाट बाजार की दाल मंडी में इंटरलॉकिंग कार्य से जुड़ा है। ग्राम पंचायत ने इस काम के लिए वर्क आईडी 130565406 के जरिए 4 लाख 88 हजार 542 रुपये सामग्री पर और 57 हजार 600 रुपये मजदूरी पर खर्च दिखाए थे। कुल मिलाकर 5 लाख 46 हजार 142 रुपये खर्च हुए थे। जांच में पता चला कि जिस जगह इंटरलॉकिंग का काम दिखाया गया था, वहां असल में कोई काम नहीं हुआ था।

इस मामले में एक और खास बात सामने आई है। ककरहवा हाट बाजार की दाल मंडी में यह इंटरलॉकिंग का काम मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में पहले ही कराया जा चुका था। इसके बावजूद, उसी जगह पर दोबारा इंटरलॉकिंग कार्य के नाम पर एक नई परियोजना बनाकर पैसे खर्च किए गए। इससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के बाद नए काम शुरू करने के लिए एक तय मंजूरी प्रक्रिया होती है। 25 और 29 मई 2026 के सरकारी आदेशों और 26 मई और 4 जून के प्रशासनिक निर्देशों के तहत, नए काम से पहले डीपीआरओ के जरिए डीएम से मंजूरी लेना जरूरी होता है। दुल्हा सुमाली के इस काम के लिए ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, फिर भी पैसे खर्च कर दिए गए।

अब मामला केवल सचिव के निलंबन तक सीमित नहीं है। 5.46 लाख रुपये का भुगतान सरकारी व्यवस्था में एक ही स्तर से सीधे नहीं होता। किसी कार्य के लिए योजना तैयार होने से लेकर स्वीकृति, तकनीकी प्रक्रिया, अनुमान, कार्य शुरू होने, सामग्री की आपूर्ति, श्रमांश दर्ज होने, कार्य की माप, सत्यापन और भुगतान तक अलग–अलग स्तरों पर अभिलेख तैयार होते हैं। इसलिए यदि मौके पर काम हुआ ही नहीं तो इन सभी अभिलेखों की जांच जरूरी होगी। सामग्री मद में करीब 4.89 लाख रुपये खर्च दिखाए गए हैं। जांच में यह देखना होगा कि सामग्री की खरीद किससे हुई, बिल और वाउचर किसके नाम पर बने, सामग्री की आपूर्ति कहां हुई, स्टॉक में उसकी एंट्री हुई या नहीं और जिस काम के लिए सामग्री दिखाई गई, वह मौके पर कहां इस्तेमाल हुई। वहीं श्रमांश के रूप में 57,600 रुपये खर्च दिखाया गया है तो श्रमिकों की उपस्थिति, कार्य दिवस और उससे संबंधित रिकॉर्ड का भी सत्यापन होना जरूरी है।

सबसे महत्वपूर्ण जांच इस बात की होगी कि कार्य की माप किसने की, माप और कार्य की स्थिति का सत्यापन किसने किया, भुगतान के लिए अभिलेख किसने तैयार किए और भुगतान को किस–किस स्तर से मंजूरी मिली। यदि काम जमीन पर हुआ ही नहीं तो सरकारी रिकॉर्ड में काम की प्रगति और खर्च कैसे दर्ज हुआ, यह जांच का केंद्रीय बिंदु होगा। पहले से मनरेगा से कराए गए कार्य के बावजूद उसी स्थल पर नई परियोजना तैयार होने से भी कई सवाल खड़े हुए हैं। परियोजना की जरूरत किस आधार पर तय हुई, स्थल का सत्यापन किसने किया और बिना डीएम की स्वीकृति के प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी, इसकी भी जांच जरूरी है। इसके साथ यह भी पता करना होगा कि ई–ग्राम स्वराज पर वर्क आईडी के जरिए खर्च दर्ज होने से पहले और भुगतान होने तक किस–किस स्तर पर जांच और सत्यापन किया गया। डीएम के निर्देश पर सचिव केशभान यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन अब निगाह इस बात पर है कि जांच भुगतान की पूरी चेन तक पहुंचती है या नहीं। अगर बिना काम के सरकारी धन खर्च दिखाया गया और भुगतान हुआ है तो केवल उस कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होना पर्याप्त होगा या उन सभी लोगों की भूमिका भी सामने आएगी, जिनके सत्यापन, संस्तुति या अनुमोदन के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई।

बच्चों की सीख को धार देंगे शिक्षक कार्यशाला में सीखे नये तरीके

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बच्चों को केवल पढ़ना और गिनना सिखाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने में प्रवाह के साथ शब्दों का अर्थ समझने और गणितीय अवधारणाओं को तर्क के साथ ग्रहण करने में सक्षम बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र हर्रैया के सभागार में लिटरेसी एवं न्यूमैरेसी विषयक एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ब्लॉक के 38 विद्यालयों से 38 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी विजय आनंद ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला का संचालन सीएसएफ की टीम ने किया। टीम के सदस्यों ने शिक्षकों को गतिविधि आधारित एवं प्रभावी शिक्षण के विभिन्न तरीकों से परिचित कराया।

प्रशिक्षण के दौरान कक्षा दो के विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण पठन क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षकों को बताया गया कि बच्चों को अक्षर एवं शब्द पहचान से आगे बढ़ाकर वाक्य को सहजता, शुद्धता और अर्थबोध के साथ पढ़ने में दक्ष बनाया जाए। गणित विषय में बच्चों की बुनियादी समझ मजबूत करने के लिए इकाई–दहाई, स्थानीय मान, संख्या पहचान और संख्या पैटर्न की अवधारणाओं को गतिविधियों के माध्यम से समझाने के तरीके बताए गए। प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया गया कि बच्चों को केवल नियम याद कराने के बजाय वस्तुओं, उदाहरणों और दैनिक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर गणितीय अवधारणाएं विकसित की जाएं। खंड शिक्षा अधिकारी विजय आनंद ने कहा कि प्रारंभिक कक्षाओं में मजबूत बुनियाद ही बच्चे की आगे की शैक्षिक यात्रा को आसान बनाती है। लिटरेसी और न्यूमैरेसी में बच्चों की दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यशाला में सीखी गई तकनीकों का कक्षा–कक्ष में नियमित प्रयोग बच्चों के सीखने के स्तर में निश्चित रूप से सुधार लाएगा।कार्यशाला में शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुए अपने अनुभव साझा किए और कक्षा–कक्ष में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की।

इस अवसर पर सीएसएफ टीम के कृतिज्ञा, सरस्वती, ऋषभ, बृजेश और मानवेंद्र, एआरपी सन्तोष कुमार शुक्ल, मनोज मिश्र, राजीव शुक्ल, काशीराम वर्मा, कार्यालय के सुनील कुमार, राकेश प्रकाश श्रीवास्तव, रिजवान, विवेकानंद शुक्ल आदि उपस्थित रहे।

कांग्रेस का महंगाई–बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला, बोले नेता– जनता की समस्याओं से नहीं है सरकार को सरोकार

संवाददाता–संतकबीरनगर। महंगाई, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को धनघटा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि बेरोजगारी के कारण युवा परेशान हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं और जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से बड़ी संख्या में युवा परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से जनहित के इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। खेती की लागत बढ़ने के बावजूद उपज की कीमत के मुताबिक किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

धरने में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाना जरूरी है। कांग्रेस ने जनहित से जुड़े स्थानीय मुद्दों के समाधान की भी मांग उठाई। वक्ताओं ने दावा किया कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और अन्य जनहित के मुद्दे लगातार लोगों के सामने चुनौती बने हुए हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव–गांव जाकर जनता की समस्याओं को उठाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में विभाजन की राजनीति देश को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। नेताओं ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अभिषेक दत्त तथा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शहला अरारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

भाकियू की बैठक में किसानों की समस्याओं पर मंथन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला

संवाददाता–संतकबीरनगर। बेलहर विकासखंड परिसर में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन की ब्लॉक इकाई की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम विश्वकर्मा ने की। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं के साथ क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया तो संगठन उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएगा। बेलहर विकासखंड परिसर में आयोजित बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम विश्वकर्मा ने अध्यक्षता की। बैठक में संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने अपने से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और उनके समाधान के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों की अलग–अलग समस्याओं पर विस्तार से बातचीत हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। संगठन की ओर से किसानों के हित से जुड़े मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के सामने रखने पर भी जोर दिया गया। किसानों ने क्षेत्र में कथित रूप से फैले भ्रष्टाचार को लेकर भी नाराजगी जताई। बैठक में इस समस्या को रोकने के लिए संगठन स्तर पर आवाज उठाने की बात कही गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं और किसान हित से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं को अगर लगातार अनदेखा किया गया तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। किसानों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के सामने समस्याओं को मजबूती से उठाने की बात कही गई।

शिवपति कॉलेज शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी गठित

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ के शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षक संघ इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। शिक्षक सभागार में हुई निर्वाचन प्रक्रिया में प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार को अध्यक्ष और शशि शेखर मिश्र को महामंत्री चुना गया। प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र की देखरेख में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद शिक्षकों ने पदाधिकारियों को बधाई दी। शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक सभागार में शिक्षक संघ इकाई की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र की देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। सभी पदों पर सहमति बनने के बाद कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। नई कार्यकारिणी में प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार को शिक्षक संघ इकाई का अध्यक्ष चुना गया। उनके अध्यक्ष बनने पर मौजूद शिक्षकों ने शुभकामनाएं दीं। शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी शिक्षक हितों से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से सामने रखेगी।

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com